

INDUSTRIAL DEVELOPMENT SCHEME, 2017

**For Himachal Pradesh
& Uttarakhand**



**Kumaun Garhwal
Chamber of Commerce & Industry**

**Continuous Industrial Development
of the State**

"Chamber House"

Industrial Estate, Bazpur Road, Kashipur-244713 (Uttarakhand)

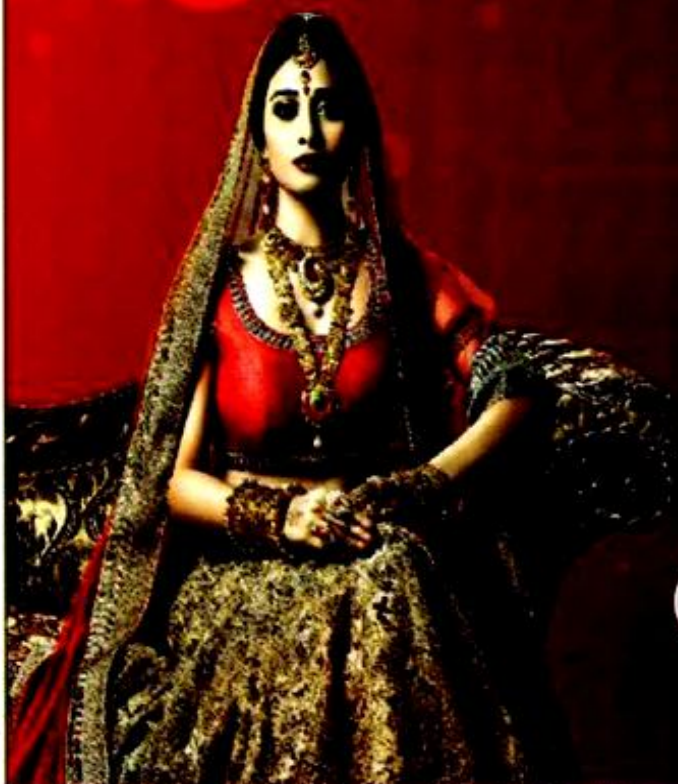
Kgcci10@gmail.com

www.kgcci.org



Bansal Jewellers®

(AN ISO 9001:2008 Certified & 100% Hallmark Jewellery Store)



Introducing
THE **NEW**
 **GENERATION**
JEWELLERY

RUDRAPUR - 42, D1-D2, Civil Lines, Ph: +91-97603 10005
HALDWANI - Bhotia Padao (Opp. Taxi Stand) Nainital Road, Ph: +91-97607 10009
E-mail: info@bansaljewellers.com & log on to www.bansaljewellers.com

Copyright © Bansal Jewellers Pvt. Ltd. 2008

INCEPTION

KGCCI was originally the brain child of some dynamic entrepreneurs who conceptualized an organization to look after the interests of mercantile community in this part of the country even before many highly industrial locations could think of a similar outfit. This location, which later became a separate State, was a tiny part of Uttar Pradesh with distinctly differing from rest of the State in geographical, climatic and cultural environments.

KGCCI was established in the year 1987 with its office located in the premises of Jindal Solvent Extraction Factory, Kashipur. During 1997, it was shifted to rented office space at the Old *Anaj Mandi*. Now the office of the KGCCI is situated in its own building in the Industrial Estate, Bazpur Road, Kashipur. The building has been named "CHAMBER HOUSE". The existing building in the location was inaugurated in 1999 by the Honorable Chief Minister of the State, Shri Narayan Dutt Tiwari. Later a new multipurpose building was constructed with appealing grandeur. This was inaugurated by Hon'ble Minister, Health & Family Welfare, Uttarakhand State, Mr. Tilak Raj Behar on March 30, 2006. The building has a well established auditorium with a seating capacity of 150 and a conference room to accommodate 50 persons. There is also a banquet hall. The building houses spacious office for the staff of the Chamber and also a small pantry to meet the needs of snacks and beverages for events held in the premises.

The KGCCI with clear vision and objectives for the industrial and economic betterment has been growing into a strong and effective association of the Trade and Industry of the State. Post 2000 when the State of Uttarakhand was born, the pace of the Industrial Development in the State quickened up. New Industrial Areas were established and many factories of different scales were installed in the State. The membership of the chamber has also been growing gradually and the present strength is about 350.

FORUM OF INTERACTION

KGCCI provides the platform for the industry and trade of Uttarakhand for interaction within themselves the Government bodies of the State and the Centre. Expert committees have been formed to deliberate on specific issues and subjects of business like company laws, taxation, finance and banking, custom & excise, infrastructure, power supplies, labour laws & human resources development, etc. Legal issues common for the industry are also taken up by the Chamber. Expert services that would benefit the members are arranged by the Chamber. Trainings, workshops and seminars are organized for the benefit of the members and the employees of the members organizations.

CREDENTIALS

KGCCI is an organizational member of:

- Power Advisory Committee of Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.
- Micro Small & Medium Enterprises Development Institute (MSME DI).
- Uttarakhand Industry Felicitation Council.
- ESTC Governing Council.
- District Level Udyog Mitra.
- State Level Udyog Mitra.
- PHD Chamber of Commerce & Industry (PHDCCI)
- Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI).
- IMC (Institute Management Committee) of Government it is at Kashipur, Haridwar, Roorkee and Dehradun, Tanakpur, Pauri etc.
- Zonal and Regional Railway Consumers Advisory Committees.

ENTERPRENEURIAL DEVELOPMENT

KGCCI, endeavors to generate spirit of self-help and promote entrepreneurial skills by spreading relevant information, organizing seminars and interaction sessions.

LEGISLATION

Information on all legislations and regulations and the changes made in them that would affect the industries is shared with all concerned members and also made available from the archives of the Chamber.

BENEFITS OF KGCCI MEMBERSHIP

- Members can avail support in representing them in specific or common issues affecting their business.
- Organizations can have publicity about their products / services through the directory of members, periodic Bulletins, E-Bulletins and other publications.
- They may gain professional insight for managing their business in a better manner.

OBJECTIVES OF THE CHAMBER:

- Representation of problems of member units to Government functionaries. (Center & State) Dissemination of rules, regulations, Circulars etc. received from Govt. to member units of the Chamber.
- Interaction of members among themselves, with the Governmental agencies and authorities on different topics from time to time.
- Supporting members in their product marketing through Trade Fairs, Expos and exhibitions at different places from time to time.
- Directory of member units with their brief business profile is published periodically for circulation amongst members, Government officials and potential customers for members.
- Publication of a Bulletin and E-Bulletin for in house circulation to keep members updated of the developments pertaining to the industry.
- Organizing of workshop, Seminars, Conferences etc. with experts on the subject from time to time.
- Certification of documents and provisioning certificates of origin for export purposes.
- Participation in Social Welfare and activities of National interests on behalf of the members.





**Industrial Development Scheme
for
Himachal Pradesh (HP)
&
Uttarakhand, 2017**



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART 1 - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुद्धवार, मई 2, 2018/वैशाख 12, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2018/VAISAKHA 12, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

फा. सं. 2(2)/2018-एसपीएस – भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में औद्योगिक इकाईयों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 की घोषणा की जाती है।

1. **स्कीम शीर्षक :** इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 कहा जाएगा।
2. **कवरेज :** इस स्कीम में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों को कवर किया जाएगा।
3. **शुरूवात की अवधि :** यह 01.04.2017 से लागू होगी तथा 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी।

4. पात्रता :

- 4.1 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में अवस्थित जैव-प्रौद्योगिकी तथा 10 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन इकाईयों सहित विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की सभी नई औद्योगिक इकाईयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाईयां इस स्कीम के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।
- 4.2 यह स्कीम अनुबंध-1 में सूचीबद्ध उद्योगों के संबंध में लागू नहीं होगी।
- 4.3 सभी पात्र औद्योगिक इकाईयां इस स्कीम के एक अथवा अधिक घटकों से लाभ प्राप्त करने की पत्र होंगी, चाहे ऐसी इकाईयां भारत सरकार की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही हों।
- 4.4 सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसंपत्तियां शामिल होंगी लेकिन भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।
- 4.5 नई औद्योगिक इकाईयां तथा व्यापक विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाईयां इस योजना के तहत पात्र होंगी। एक नई इकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
 - (क) पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।
 - (ख) पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।
 - (ग) यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और/अथवा यह पहले से मौजूद इकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नया नाम एवं स्टाइल दिया गया हो।

5. परिभाषाएं

- (क) 'वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुवात' से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरुवात जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुसार हों।

- (ख) 'प्रभावी कदम' से आशय, निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से है :-
- (a) औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गई पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का भुगतान किया जा चुका हो।
 - (b) फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो।
 - (c) औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए फर्म आर्डर दिया जा चुका हो।
- (ग) 'तैयार माल' का अर्थ है वस्तुतः किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित माल जिसके लिए वह पंजीकृत है।
- (घ) 'औद्योगिक इकाई' का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित इकाई के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा क्षेत्र इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।
- (ङ) 'विनिर्माण कार्य' का अर्थ है वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है (i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नए तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढांचे के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।
- (च) 'योग्य सेवा क्षेत्र इकाई' सेवा क्षेत्र में एक उद्यम है, जिसमें काफी पूंजी व्यय की आवश्यकता है और इसमें अत्यधिक रोजगार सृजन क्षमता है।
- (छ) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने 01 अप्रैल, 2017 को अथवा इसके बाद परन्तु 31 मार्च, 2022 से पहले औद्योगिक इकाई के रूप में डीआईपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण से 18 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करना होगा।
- (ज) 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' का मतलब एक औद्योगिक इकाई जिसने 01.04.2017 से पहले व्यावसायिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया है।
- (झ) 'पर्याप्त विस्तार' का अर्थ है क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा परिवर्तन के प्रयोजन के लिए औद्योगिक इकाई की संयंत्र एवं मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ोतरी।
- (ञ) 'भौतिक कार्यशील पूंजी' को फैक्ट्री द्वारा लेखा वर्ष के अंतिम दिवस को अपने स्वामित्व अथवा धारित अथवा नियंत्रणाधीन समस्त भौतिक माल सूचियों यथा सामग्रियां, ईंधन एवं स्नेहक, भंडारण आदि जिसका इस्तेमाल स्वयं फैक्ट्री द्वारा

विनिर्मित उत्पाद में अथवा प्रसंस्करण हेतु अन्य को फैक्ट्री द्वारा आपूरित उत्पाद में इस्तेमाल होता है, को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। भौतिक कार्यशील पूंजी में सामग्री भंडार, ईंधन एवं अन्य भंडार आदि, जिसे स्पष्ट तौर पर पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया हो, अर्द्ध-तैयार माल तथा अन्यो का प्रगति पर कार्य तथा फैक्ट्री द्वारा बनाया गया माल जो लेखा वर्ष के अंत में बिक्री के लिए तैयार हो, शामिल है। तथापि, इसमें प्रसंस्करण हेतु अन्यो द्वारा फैक्ट्री को आपूरित सामग्री भंडार, ईंधन, भंडार आदि शामिल नहीं है। फैक्ट्री द्वारा आपूरित कच्चे माल से अन्यो द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल तथा उनके द्वारा धारित माल को शामिल किया गया है तथा अन्यो द्वारा आपूरित कच्चे माल से फैक्ट्री द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल को शामिल नहीं किया गया है।

- (ट) 'कच्चा माल' का अर्थ है कि तैयार माल के विनिर्माण में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुतः अपेक्षित तथा इस्तेमाल किया गया कच्चा माल जिसके लिए अनुरोध किया गया है।
- (ठ) 'कार्यशील पूंजी' उपर्युक्त पैरा (झ) में यथा परिभाषित भौतिक कार्यशील पूंजी तथा हस्तगत नकदी तथा बैंक में जमा तथा लेखा वर्ष के अंत में देय राशि पर प्राप्त राशि के निवल शेष की कुल राशि है।

तथापि, अन्य अप्रयुक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा, समयावधि पर ध्यान दिए बिना मियादी जमा, स्थिर परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए अग्रिमों, ऋणों तथा स्वामियों एवं भागीदारों द्वारा उनके प्रयोजन एवं समयावधि पर ध्यान दिए बिना अग्रिम, ब्याज सहित दीर्घावधि ऋणों तथा निवेशों को कार्यशील पूंजी से बाहर रखा गया है।

- (ड) 'संयंत्र एवं मशीनरी' में स्थल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होंगे। अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस स्कीम के तहत सहायता के पात्र नहीं हैं। स्कीम और किसी विनिर्माण इकाई में शामिल किए जाने वाले/हटाए जाने वाले घटक अनुबंध-॥ में दिए गए हैं। मशीनरी की खरीद सामान्य मूल्य पर खुले बाजार से की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या यह खरीद नजदीकी प्राप्य मूल्य प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किसी संबंधित पक्ष से की गई है।

6. पात्र औद्योगिक इकाईयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे :

1. ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईसी)
2. केन्द्रीय व्यापक बीमा राजसहायता (सीसीआईआई)

6.1 एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी जिसके अध्यक्ष सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग होंगे तथा इसमें व्यय विभाग के सचिव तथा नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा उस उद्योग के मामले से जुड़े भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य जहां पर इस स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु इन्सेन्टिव का दावा करने वाली लाभार्थी इकाई अवस्थित है, के संबंधित मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग) शामिल होंगे। प्रोत्साहनों के प्रस्तावों की जांच करते समय लागत पहलु, परियोजना व्यवहार्यता, बैंक योग्यता तथा प्रोत्साहन प्रदाता जोखिम पूंजी जैसे कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के अन्तर्गत आने वाली पात्र औद्योगिक इकाईयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2 ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)

6.2(क) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की कहीं पर भी अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाईयों और पर्याप्त विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को ऋण के लिए (सीसीआईआई) 5 करोड़ रु0 की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में पात्र निवेश के 30 प्रतिशत के हिसाब से केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

6.2(ख) डीआईपीपी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सहायता प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने से पहले किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना लागत का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परियोजना रिपोर्ट पर पूंजीगत व्यय और मंजूरी पत्र तैयार होने के संबंध में बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर संयंत्र एवं मशीनरी के काम शुरू करने पर सम्पूर्ण सहायता जारी कर दी जाएगी।

6.2(ग) सरकार की लागत बढ़ने की अवस्था में सहायता राशि बढ़ाने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। परियोजना के समय-पूर्व बंद होने अथवा बीच में ही छोड़े जाने की अवस्था में सरकार द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण सहायता को डीआईपीपी को लौटाना होगा।

6.3 केन्द्रीय व्यापक बीमा राजसहायता (सीसीआईआई)

6.3(क) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में किसी भी स्थान पर अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाईयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए भवन परिसरों तथा संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रमियम की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

6.3(ख) बीमा राजसहायता के प्रयोजनार्थ, औद्योगिक इकाई का अर्थ है कोई उद्योग जो अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि नीति 'ग' में शामिल है। यह नीति प्रस्तावक द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर बीमा कंमनी द्वारा जारी की जाएगी।

7. अनिवार्य अपेक्षा

- 7.1 इस स्कीम के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ हेतु पात्रता से पहले सभी पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल के जरिए पूर्व पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में, एक ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया विकसित की जाएगी जिसके अन्तर्गत आवेदकों को डीपीआर के साथ आवेदन जमा कराने होंगे।
- 7.2 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम के लिए ऑनलाईन पोर्टल के इस्तेमाल हेतु अलग से विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।
- 7.3 पंजीकरण/सिद्धान्ततः अनुमोदन के संबंध में इस समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाई की प्राथमिक पात्रता, बजट की उपलब्धता पर विचार करेगी तथा स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता का निर्णय करेगी। कोई भी औद्योगिक इकाई हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण अथवा लाभों का दावा करने का हक नहीं रख सकेगी बशर्ते कि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित हो। राजसहायता के भुगतान में विलम्ब की वजह को लेकर किसी प्रकार के ब्याज का किसी इकाई द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता। इस स्कीम के लाभार्थी को इस स्कीम के शर्त तथा निबन्धन का अनुपालन करने का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7.4 इन इकाईयों को अनुमोदन प्राप्त होने के 18 माह की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
- 7.5 जिन इकाईयों ने 01.04.2017 को अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है उन्हें 30.09.2018 तक डीआईपीपी में पंजीकरण की अनुमति होगी।

8. नोडल एजेंसी

- 8.1 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचपीएसआईडीसी) और उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के लिए स्कीम के विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण हेतु एक नोडल एजेंसी होगी। एचपीएसआईडीसी और एसआईडीसीयूएल पात्र औद्योगिक इकाईयों के नामित बैंक खातों में केवल ई-ट्रांसफर के जरिए राजसहायता जारी करेगा।

9. दावों की जांच प्रक्रिया

- 9.1 डीआईपीपी में पूंजी निवेश प्राप्ताहन के अन्तर्गत प्राप्त राजसहायता के दावों की एक पंजीकृत स्वतंत्र लेखा-परीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-समीक्षा की जाएगी। एचपीएसआईडीसी और एसआईडीसीयूएल द्वारा हर बार जारी किए गए दावों के 10 प्रतिशत लेखा परीक्षा पश्चात जांच की जाएगी। डीआईपीपी के मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जारी किए गए राजसहायता दावों के 20 प्रतिशत की लेखा परीक्षा करेंगे।
- 9.2 सरकार के पास इस स्कीम के किसी भाग में जनहित में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 9.3 इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करने तथा आवश्यक अनुदेश जारी करने की अपेक्षा होगी।

10. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार

- 10.1 यदि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्था को इस बात की पुष्टि हो कि किसी औद्योगिक इकाई ने जाली सूचना देकर धोखे से राजसहायता प्राप्त की है, अथवा यदि वह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के 5 वर्ष के भीतर उत्पादन बंद कर देती है तो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल उस इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ऐसी इकाई को अनुदान अथवा राजसहायता लौटाने के लिए कह सकते हैं। यह राजसहायताएं, डिजिटल भुगतान के जरिए जारी की जाएंगी तथा एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल लाभार्थी औद्योगिक इकाईयों के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सभी सूचना एकत्रित करेगा जो लाभार्थी इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से इस संबंध में एक शपथपत्र ले सकता है। स्कीम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली लाभार्थी इकाई को राजसहायता के वितरण से पूर्व औद्योगिक इकाई और एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल के बीच एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
- 10.2 दी गई सूचना को जान बूझकर छुपाने अथवा तीसरे पक्ष के जरिए धोखा करने अथवा गैर हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड उत्पादन के लिए दावे करने अथवा इसी प्रकार के कदाचार करने पर औद्योगिक इकाई के भावी दावे जब्त कर लिए जाएंगे तथा पूर्व में दी गई सभी राजसहायताओं की वसूली 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ की जाएगी।

- 10.3 केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)/संबंधित राज्य सरकार / वित्तीय संस्था के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी औद्योगिक इकाई के स्वामी को आंशिक अथवा समग्र राजसहायता प्राप्त करने के बाद किसी औद्योगिक इकाई के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई के स्वामित्व को परिवर्तित करने अथवा इकाई के आकार में बदलाव करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के अंदर इसके कुल तय पूंजी निवेश के बड़े हिस्से को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इकाई द्वारा स्थल अथवा सम्पर्क सूत्र में किसी परिवर्तन के संबंध में डीआईपीपी को सूचित करना भी अपेक्षित है।
- 10.4 उन सभी इकाईयों जिनको एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल द्वारा राजसहायता वितरित की गई है, दिए गए आशय हेतु सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रप. 12 (ग) में राजसहायता के इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को संबंधित वित्तीय संस्था/राज्य सरकार द्वारा अंतिम किश्त पूर्ण राशि प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
- 10.5 राजसहायता प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक औद्योगिक इकाई को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग / संबंधित राज्य सरकार को उत्पादन के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन जारी रखने के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करनी होगी।

11. विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

डॉ वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग और नीति आयोग
2. हिमाचल प्रदेश / उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव
3. हिमाचल प्रदेश / उत्तराखण्ड राज्य के सचिव (उद्योग)
4. हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० (एचपीएसआईडीसी) शिमला
5. उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसीयूएल) देहरादून

प्रति प्रेषित :

1. मंत्रीमण्डल सचिवालय
2. प्रधानमंत्री कार्यालय

निषेध सूची

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्योग लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

- (i) केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से संबंधित हैं।
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।
- (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ. 705 (ई), दिनांक 02.09.1999 तथा एस. ओ. 698 (ई) दिनांक 17.06.2003 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।
- (iv) पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाला सामान।
- (v) पौधरोपण, शोधशालाएं तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन इकाईयां।
- (vi) कोक (कैलसाइण्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाइ ऐश, सीमेंट, स्टील रोलिंग मिल।
- (vii) पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां इस स्कीम के अन्तर्गत राज सहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।
- (viii) उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भण्डारण के दौरान संरक्षण, साफ-सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्धन कार्यकलापों की अनुमति होगी।
- (ix) सरकार द्वारा कभी आवश्यक समझे जाने पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध सूची में शामिल कोई अन्य उद्योग/कार्य। यह ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।
- (x) गोल्ड और गोल्ड डोर।

अनुबंध-II

- क. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु शामिल किए जाने वाले घटक :**
- कर और शुल्क सहित औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी की लागत अर्थात विनिर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उत्पादन उपकरण की लागत।
 - उत्पादक उपकरण जैसे टूल्स, जिग्स, डाई और मोल्ड, इन्श्योरेन्स प्रीमियम आदि की कर और शुल्क सहित लागत।
 - संयंत्र की ओर जहां मीटर लगाया गया है, से तैयार वस्तुओं के उत्पादन/डिस्पैच वाले स्थान तक संयंत्र के प्रचालन हेतु आवश्यक इलैक्ट्रिकल घटक (अर्थात एच.टी. मोटर, एल.टी. मोटर, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर, रिले, सर्किट ब्रेकर, पैनल बोर्ड, स्विच गियर)।
 - आपूर्तिकर्ता के परिसर से इकाई के स्थान तक संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण लाने के लिए भुगतान किया गया मालभाड़ा।
 - भुगतान किया गया ट्रांजिट इन्श्योरेन्स प्रीमियम
 - उस स्थान तक माल को ढोने में निवेश की गई राशि जहां कच्चे माल के परिवहन और तैयार माल के विपणन के लिए उसका उपयोग किया गया।
- ख. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु निम्नलिखित घटकों को शामिल नहीं किया जाएगा।**
- माल चढ़ाने और उतारने का भाड़ा
 - संयंत्र और मशीनरी के लिए शेड/भवन
 - डीजी सेट, उत्खनन/खनन संबंधी उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, ऊपर क (iii) में जिनका उल्लेख किया गया है, उन्हें छोड़कर अन्य इलैक्ट्रीकल घटकों जैसी विविध नियत परिसंपत्तियां
 - कच्चे माल और अन्य उपभोग्य भण्डारों सहित कार्यशील पूंजी
 - चालू करने संबंधी लागत
 - कैपिटल पावर प्लांट
 - भण्डारण उपकरण
 - वजन तोलने का उपकरण (वे ब्रिज), प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण
- ग. विनिर्माण क्षेत्र में उत्थापन एवं स्थापना संबंधी प्रभारों की स्वीकार्यता**
- उत्थापन एवं स्थापना संबंधी प्रभार का भुगतान, वास्तविक आधार पर किया जाएगा और औद्योगिक इकाई को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन टिप्पणी में निर्धारित लागत तक सीमित होगा। ■

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Industrial Policy & Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2018

F. No. 2(2)/2018-SPS.- The Government of India is pleased to announce Industrial Development Scheme for the State of Jammu & Kashmir to boost industrialization.

1. **Scheme title :** The scheme will be called Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh (HP) & Uttarakhand, 2017.
2. **Coverage :** The scheme will cover the State of H.P. & Uttarakhand
3. **Commencement and duration :** It will be effective from 01.04.2017 and will remain in force up to 31.03.2022.
4. **Eligibility :**
 - 4.1 Unless otherwise specified, all new industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion in manufacturing sector and services sector including Bio-technology and Hydel Power Generation Units up to 10 MW located in the State of H.P. & Uttarakhand will be eligible for incentives under the scheme.
 - 4.2 The scheme shall not be applicable to the industries listed in the **Annexure – I.**
 - 4.3 All eligible industrial units will be entitled to benefits under one or more components of this scheme, even if such units are getting benefits under other schemes of the Government of India.
 - 4.4 Plant and Machinery for the service sector industrial unit shall include cost of construction of building and all other durable physical assets basic to the running of that particular service industry but exclude cost of land and consumables, disposables or any other item charged to revenue.
 - 4.5 New industrial units and existing industrial units underaking substantial expansion shall be eligible under the scheme. A new unit will be required to fulfil the following conditions :
 - (a) it is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.
 - (b) it is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.

- (c) it has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.

5. Definitions

- (a) **Commencement of Commercial Production** means starting of manufacture of finished products on commercial scale which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery and on that day the plant must be ready in all respects for manufacture of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available and as per date of registration with Central Excise/Goods and Services Tax (GST) authorities.
- (b) **Effective steps** means one or more of the following steps:-
- (i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.
 - (ii) that any part of the factory building has been constructed.
 - (iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.
- (c) **Finished Goods** means the goods actually produced by an industrial unit and for which it is registered.
- (d) **Industrial Unit** means any industrial undertaking or eligible service sector unit, other than that run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Services Tax.
- (e) **Manufacturing Activity** means 'an activity which brings about a change in non-living physical object or article or thing (i) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (ii) bringing into existence of a new and distinct object, article or thing with a different chemical composition or integral structure'.
- (f) **Eligible Service Sector Unit** is an enterprise in the services sector that requires significant capital expenditure and has significant employment generation potential.
- (g) **New industrial unit** means an industrial unit which registers itself on DIPP portal on or after the first day of April, 2017 but not later than 31st day of March, 2022. Such units have to commence commercial production/ operation within 18 months of registration.

- (h) **'Existing Industrial unit'** means an industrial unit which commences commercial production/ operation before 01.04.2017.
- (i) **'Substantial expansion'** means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in Plant & Machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity / modernization and diversification.
- (j) **'Physical Working Capital'** is defined to include all physical inventories owned, held or controlled by the factory as on the closing day of the accounting year such as the materials, fuels & lubricants, stores etc., that enter into products manufactured by the factory itself or supplied by the factory to other for processing. Physical working capital also includes the stock of materials, fuels & stores etc., purchased expressly for re-sale, semi-finished goods and work in progress on account of others and goods made by the factory which are ready for sale at the end of the accounting year. However, it does not include the stock of the materials, fuels, stores etc. supplied by others to the factory for processing. Finished goods processed by others from raw materials supplied by the factory and held by them are included and finished goods processed by the factory from raw materials supplied by others are excluded.
- (k) **'Raw Material'** means any raw materials actually required and used by an industrial unit in manufacturing of the finished goods for which it is requested.
- (l) **'Working Capital'** is the sum total of the physical working capital as defined in Para (j) above and the cash deposits in hand and at bank and the net balance of amounts receivable over amounts payable at the end of the accounting year.

Working capital, however, excludes unused overdraft facility, fixed deposits irrespective of duration, advances for acquisition of fixed assets, loans and advances by proprietors and partners irrespective of their purpose and duration, long term loans including interest thereon and investments.
- (m) **'Plant and Machinery'** shall cover the cost of newly purchased industrial plant and machinery as erected at site. Relocated / Recycled / Refurbished plant and machinery is not eligible for assistance under the Scheme. Components to be included / excluded for the purpose of scheme and for a manufacturing unit is at **Annexure II**. The purchase of machinery should be from open market at normal market price. It will be ascertained whether the purchase has been made from a Related Party without following an arms-length price discovery.

6. The following incentives will be provided to eligible industrial units on reimbursement basis:

1. Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)
2. Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

6.1 There will be an Empowered Committee chaired by Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion with Secretaries of D/o Expenditure, representative of NITI Aayog and Secretary of the concerned Ministries/Departments of Government of India dealing with the subject matter of that industry as its members as also the concerned Chief Secretary/Secretary (Industry) of the State where the beneficiary unit claiming incentive is located for selection of beneficiaries under the scheme. While examining the proposals for incentive, due consideration will be given to factors like cost disadvantage, project viability, bankability, employment generation and promoters' risk capital. Preference will also be given to eligible industrial units under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

6.2 Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)

6.2(a) : All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion in the manufacturing and service sector located anywhere in the States of H.P. and Uttarakhand will be provided Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC) @ 30% of the investment in plant and machinery with an upper limit of Rs.5.00 crore.

6.2(b) : The project cost will need to be appraised by a Scheduled Commercial Bank or Financial Institution before the proposal of assistance is approved by the Empowered Committee of DIPP. Full assistance will be released on the basis of certificate issued by Competent Authority of the bank that the capex on the project report and sanction thereof is in place and Plant & Machinery has been put to use.

6.2(c) : The government does not commit itself to increase in the scale of assistance in case of cost escalation. In case the project is foreclosed or abandoned midway the entire assistance released by government will be refunded to DIPP.

6.3 Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

- 6.3(a) :** All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the states of H.P & Uttarakhand will be eligible for reimbursement of 100% insurance premium on insurance of building and Plant & Machinery for a maximum period of 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation.
- 6.3(b) :** For the purpose of insurance incentive, 'industrial unit' shall mean any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs. The policy shall be issued by the Insurance Company on market valuation to be declared by the proposer.

7. Mandatory requirement

- 7.1** This Scheme requires that all eligible industrial units would have to register under the Scheme with Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, through the DIPP portal prior to being eligible for any benefit under this scheme. In this regard, an online application process shall be developed under which the applicants have to submit applications along with the DPR.
- 7.2** The Department of Industrial Policy and Promotion would separately issue detailed instructions for the use of online portal for Industrial Development Scheme for H.P & Uttarakhand and registration of eligible units.
- 7.3** The final grant of registration/in-principle approval will be decided by the Committee, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the industrial unit, availability of budget and decide the eligibility for registration under the Scheme. No Industrial unit will have the right to register under Industrial Development Scheme for H.P & Uttarakhand or claim the benefits unless it is specifically approved by the Central Government. No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme.
- 7.4** The units should start commercial production within 18 months of approval.
- 7.5** Units which have commenced production on or after 1.4.2017 will be allowed to register with DIPP upto 30.9.2018.

8. Nodal agency

8.1 The Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd.(HPSIDC) and State Industrial Development Corporation of Uttarakhand (SIDCUL) will be the nodal agencies for disbursement of incentives under various components of the Scheme for the States of H.P & Uttarakhand respectively. HPSIDC and SIDCUL will release incentive only through e-transfer to designated bank accounts of the eligible industrial units.

9. Process of Scrutiny of claims

- 9.1 Incentive claims under Capital Investment Incentive received in DIPP will be pre-scrutinized by a recognized independent audit agency. HPSIDC and SIDCUL will conduct post-audit of 10% of claims released every time. The Chief Controller of Accounts of DIPP will also conduct post-audit of 20% of incentive claims released in each financial year.
- 9.2 Government reserves the right to modify any part of the Scheme in public interest.
- 9.3 All concerned Ministries/Department of Government of India are required to amend their respective Acts/ Rules/ Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

10. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions

- 10.1 If the Central Government/State Government/Financial Institution concerned is satisfied that an industrial unit has obtained incentive(s) by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production/ operation within 5 years after commencement of commercial production/ operation, the Central Government/ State Government / HPSIDC/SIDCUL may ask the unit to refund the grant or incentive after giving an opportunity of being heard to the unit. The incentive(s) will be released through digital payment and would collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary industrial unit. HPSIDC/SIDCUL may take an affidavit in this regard from authorized signatory of the beneficiary unit. An indemnity bond may also be signed between the industrial unit and HPSIDC/SIDCUL prior to disbursement of incentives, providing for undertaking on the part of the beneficiary unit to comply with all the requirements of the scheme.
- 10.2 Concealment of input supplies or routing of third party or non-Himachal Pradesh/Uttarakhand production for claims or malpractices of similar kinds will render the industrial unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous subsidies with interest @ 15% per annum.

- 10.3 Without taking prior approval of the Union Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) /State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the incentive will be allowed to change the ownership of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production. The unit will also be required to keep DIPP informed about change in location or contact information.
- 10.4 In respect of all units to whom the incentive is disbursed by HPSIDC/SIDCUL, certificate of utilization of the incentive(s) in Form 12(C) of General Financial Rules, 2017 for the purpose for which it was given shall be furnished to the Department of Industrial Policy and Promotion by the financial institution/State Government concerned, within a period of three months from the date of receipt of the last installment/full amount.
- 10.5 After receiving the incentive(s), each industrial unit shall submit Annual Progress Report (APR) to the Department of Industrial Policy and Promotion/ State Government concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.
11. Detailed guidelines shall be issued separately.

Dr. VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Copy for information and necessary action to:

- (i) All Ministries/Departments of the Government of India and NITI Aayog.
- (ii) Chief Secretary of the State of Himachal Pradesh/Uttarakhand
- (iii) Secretary (Industries) of State of Himachal Pradesh/Uttarakhand.
- (iv) Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd. (HPSIDC), Shimla.
- (v) State Industrial Development Corporation of Uttarakhand, Dehradun

Copy also to:

- (i) Cabinet Secretariat
- (ii) PMO

Annexure – I**Negative List :**

The following industries will not be eligible for benefits under Industrial Development Scheme, for H.P & Uttarakhand 2017:

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705 (E) dated 02.09.1999 and S.O. 698 (E) dated 17.6.2003.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
- (v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
- (vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash, Cement, Steel Rolling Mills
- (vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.
- (viii) Low value addition activities like preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.
- (ix) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.
- (x) Gold and gold dore.

Annexure-II**A. Components to be included for computing the value of Plant and Machinery under CCIAC in the manufacturing sector :**

- (i) Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.
- (ii) Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and moulds, insurance premium etc. including taxes and duties.
- (iii) Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/ dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).
- (iv) Freight charges paid for bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.
- (v) Transit Insurance premium paid.
- (iv) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilized for transport of raw materials and marketing of the finished products.

B. Components which will not be considered for computing the value of Plant & Machinery under CCIAC in the manufacturing sector :

- (i) Loading and unloading charges
- (ii) Sheds/ buildings for Plant & Machinery
- (iii) Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation/ Mining equipments, handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.
- (iv) Working Capital including Raw Material and other consumable stores.
- (v) Commissioning cost
- (vi) Captive Power Plants
- (vii) Storage equipments
- (viii) Weigh bridge, Laboratory testing equipment.

C. Admissibility of erection and installation charges in the manufacturing Sector

Erection and installation charges will be payable on actual basis and will be restricted to the cost indicated in the Appraisal Note of the Financial Institutions which provided loan to the industrial unit.





Important Phone Numbers

of

Uttarakhand Government

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government

Name	Office	Fax	Mobile
Dr. Krishna Kant Paul His Excellency Governor of Uttarakhand Raj Bhawan, Dehradun	2757403,	2750014	
Cabinet of MINISTERS			
Shri Trivendra Singh Rawat Hon'ble Chief Minister	2650433 2716262	2712827	
Vidhan Sabha Bhawan	2665497 2665100	2666166	
Shri Satpal Maharaj Irrigation, Flood Control, Minor Irrigation, Rain Water Harvesting, Water Management, India-Nepal-Uttarakhand River Projects, Tourism, Pilgrimage and Religious Fairs, Culture	2666377	2666380	9810990009
Shri Prakash Pant Parliamentary Affairs, Legislative Affairs, Languages, Finance, Commercial Tax, Stamp and Registration, Entertainment Tax, Excise, Drinking Water and Sanitation, Sugarcane Development and Sugar Industries	2665088	2665988	9412095511
Shri Harak Singh Rawat Forests and Wildlife, Environmental and Solid Waste Management, Labour, Employment, Industrial Training, Ayush, Ayush Education	2665155	2665399	9411114793
Shri Madan Kaushik Urban Development, Housing, Rajiv Gandhi Urban Housing Scheme, Census, Rehabilitation, Elections,	266304	266308	9837213339
Shri Yaspal Arya Transport, Social Welfare, Minority Welfare, Students Welfare	2666766	2665900	9997196151
Shri Arvind Pandey School Education, Adult Education, Sanskrit Education, Sports, Youth Welfare, Panchayati Raj	2655080	2665121	9412089301
Shri Suboth Uniyal Agriculture, Agriculture Marketing, Agriculture Education, Agriculture Processing, Silk Development, Plantation and Horticulture	2666671	2665855	9412077900

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government



Smt. Rekha Arya Minister of State. (Independent Charge) Womens Welfare and Child Development Animal Husbandry, Sheep and Goat Husbandry Fodder and Meadows Development, Fisheries	2665111	2665880	8395889380
--	---------	---------	------------

Shri Dhan Singh Rawat Minister of State. (Independent Charge) Co-operatives, Higher Education Dairy Development, Protocol	2666410	2666411	8650000797
---	---------	---------	------------

SECRETARIAT

Chief Secretary

Shri Utpal Kumar Singh	2712100 2712200	2712500	
-------------------------------	--------------------	---------	--

Additional Chief Secretary

Dr. Ranveer Singh Higher Education, Excise, Bhend evem Bakri Palan, Infrastructure Development Commissioner, Milk Development	2712057	2712803	9412992136
---	---------	---------	------------

Shri Om Prakash Additional Chief Secretary Hon'ble Chief Minister, PWD, Medical Health and Family, Medical Education, Training and Technical Education	2712066	2714106	
--	---------	---------	--

Principal Secretaries

Shri Alok Kumar Verma Justice	2712808	2712115	9411100044
---	---------	---------	------------

Smt. Radha Raturi Finance, Personnel, Women Empowerment & Child, Personnel Department	2712055	2712014	9412992134
--	---------	---------	------------

Smt. Manisha Pawar Village Development, Panchayati Raj, Pichada Kshetra Vikas, Gramya Talab Vikas Minor, Small and Medium Industries	2714389	2712095	9917003339
--	---------	---------	------------

Shri Anand Vardhan Irrigation, Small Irrigation, Food & Civil Supply, Soldier Welfare, Secretariat Administration	2712802	2712096	8171112233
--	---------	---------	------------

SECRETARIES

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government



Dr. Bhupendra Kaur Aolakh	2712097	2713532	7055999109
Shri Amit Singh Negi Hon'ble Chief Minister, Finance, External Aided Schemes, Disaster Management,	2711439	2719925	7895312007
Smt. R. Minakshi Sundram Animal Husbandry, Fisheries, Tourism, Milk & Milk Development, Culture, Dharmik Mela	2712012	2655166	7060818771
SECRETARY INCHARGE			
Smt. Radhika Jha Hon'ble Chief Minister, City Development, Energy, Alternative Energy	2711474	2712809	8979491100
Shri D. Senthil Pandian Transport, Agriculture Education, Horticulture, Rural Development	2714246	2715877	8650020003
Shri Vijay Kumar Dodhial General Administration, Minority Welfare	2712064	2712027	9927699817
Shri Dilip Javalkar Sugar Cane, CEO Smart City	2714105		8395889234
Shri Harvans Singh Chugh Ayush and Ayush Education, Labour & Employment Sports & Youth Welfare, Revenue	2719917	2655458	8395889040
Shri Chandra Shekhar Bhatt Information, School Education	2712437		9837028636
Shri Arvind Singh Hayanki Forest and Environment, Water	2712112	2655867	9412057727
Smt. Usha Shukla Language, Census, Sanskrit Education	2713530		9927699315
Shri Ravinath Raman Science & Bio Technology, Home, Social Welfare, Prison	2710791	2712248	8395889077
ADDITIONAL SECRETARY			
Dr. Pankaj Kumar Pandey Employment, Labour & Employment, Medical Health and Family, Neutrition Development	2710685		9837911999
Shri Ranjeet Kumar Sinha Niyojan	2659850		9927699701
Shri Indudhar Borai Secretariat Administration, General Administration	2656074		8395889105

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government



Shri Vinod Prasad Raturi Secretariat Administration, Sanskrit Education	2711226		9927699808
Shri Hari Chand Semwal Transport, Panchayati Raj, Excise	2719934		7830000513
Shri Ashok Kumar Teerthatan Prabandhan, Dahrmik Mela	2712001		8395889122
Shri V. Sanmugam PWD, Social Welfare	2712004	2712004	9927699403
Dr. R. Rajesh Kumar Minor, Small And Medium Industries Industrial Development	2719912	2719912	8755519291
Shri Bhupal Singh Manral Home, Personnel, Programme Implementation	2712950		9927699701
Shri Aridhar Babu Adddanki Finance	2713944	2713944	9927699691
Shri Vinay Shankar Pandey State Property	2719924		8475009815
Shri Vinod Kumar Suman City Development, Mining	2712900		8476007607
Dr. Raghav Langer Payjel, Additional Chief Officer P.M.G.S.Y.	2712810		9557639429
Shri Savin Bansal Higher Education, Tourism, Dharmaswa, Housing & Urban Development, Disaster Management	2712000		9720070007
Shri Yougal Kishor Pant Village Development	2719918		7500650000
Shri Ranveer Singh Chauhan Energy, Food & Civil Supply	2715981		7055046699
Shri Atul Kumar Gupta Punargathan	2712093		9927699326
Smt. Swati S. Bhadoria Secretary	2712113		8395889072
Shri Pooran Singh Rawat Home	2713531		9927699863
Smt. Vimmi Sachdeva Women Empowerment & Child Development	2711718		9412051340

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government



Shri Manoj Chandran Social Welfare	2714104		9837851572
Smt. Minakshi Joshi Forest and Environment	2719911		7055999023
Shri Arunendra Singh Chauhan Information Technology, Finance, Suraj, Corruption Abolition	2712013		9927699652
Shri L. N. Pant Finance	2712262		9412155749
Shri B. B. Mathpal Finance	2712807	2712807	7055602886
Shri Ram Vilas Yadav Village Development	2654980		7523999999
Cap. Alok Shekhar Tiwari Primary Education, Secondary Education	2710560		8395889070
Tulsi Ram Village Development	2712092		8395889092
Bal Mayank Mishra Revenue, Animal Husbandry, Fisheries, Milk Development, Women Dairy	2712965		8395889091
Surya Mohan Nautiyal Sports & Youth Welfare	2713557		9927699249
Lalit Mohan Rayal Hon'ble Chief Minister	2656068		9411534400
Dr. Meharban Singh Bisht Hon'ble Chief Minister	2655912		8057308608
Shri Mahendra Singh Koshiva Justice	2711384		9412364728
Shri Bharat Bhusan Pandey Legislative and Parliamentary Affairs	2665164	2665164	9411107769
Arjun Singh Secretariat Administration, Finance, Payjal	2712019		9927699306
Tikam Singh Panwar Horticulture	2712050		9927699466
G. B. Oli Ayush, Rural Development	2712026	2712113	9837015241

J. P. Joshi Revenue	2651833	7055999111
B. R. Tamta Language, Census	2712451	9927699028
Pradeep Singh Rawat Hon'ble Chief Minister, Sugarcane Soldier Welfare, PWD	2654954	9927699887
Devendra Paliwal Irrigation, Small Irrigation	2712918	9927699015
Dhirendra Singh Datal Jalagam	2715288	9927699644
Sunil Sripanthari Personnel, Housing	2655044	9927699018
Subhash Chandra Secretariat Training Institute	2713553	9927699522
Dharmendra Singh Home, Protocol	2713810	7055999030

* * *

Member of Parliament, Uttarakhand

Smt. Mala Rajlaxmi Shah Tehri Garhwal	9811670271
Major General Bhuvan Chandra Khanduri Garhwal	9013869485
Shri Bhagat Singh Koshyari Nainital	9868181004
Dr. Ramesh Chandra Pokhariyal 'Nishank' Haridwar	9837017071, 9456597100
Shri Ajay Tamta Almora	9456590857, 9013869486

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government



COMMISSIONER & OFFICERS, DEHRADUN (0135)

Commissioner, Garhwal Division	2655981	
Commissioner, Commercial Tax	2763131	2712001
Chief Information Commissioner	2675780	2675779
Director General, Information & Public Relation Deptt.	2662970	2662970
Chief Development Officer	2712569	2712569
District Magistrate	2622389	2720025
Directorate of Industries, Uttarakhand	2728227	2728226
Director General of Police	2712082, 2714656	2712080
District Industries Centre	2728226	2728226
District Information Officer	2656508	2656508
Garhwal Mandal Vikas Nigam	2740896, 2746817	2746847
Dy. Inspector General of Police	2716201	2710925
Member Secreatry, UERC	2643799	2641314
Sr. Superintendent of Police	2716203	2716204
State Infrastructure Industrial Development Corporation (SIIDCUL)	2708100, 2608092	2708109
Uttarakhand Elect.Regulatory Commission	2643755	2641314
Uttarakhand Jal Viduit Nigam	2763808	2763508
Uttarakhand Power Corporation Ltd.	2763672	2763821

NAINITAL (STD Code No. : 05942)

Commissioner, Kumaun Division	235750	236041
Chief Medical Officer	235285	239281
Chief Development Officer	248311	248311
Chief Conservator Forest, Kumaun	236218	
District Magistrate	235684	236305
District Information Officer	235605	235605
District Industries Centre,HLD	220669	280274
Dy. Commissioner, Trade Tax, HLD	222032, 7055602909	
Regional Tourism Officer	235337	
District Horticulture Officer	247266	
Divisional Forest Officer	236790	236790
Executive Engineers, PWD, HLD	235728, 232030	235728
High Court, Nainital	231691	231692
Inspector General of Police, Kumaun, HLD	235456	233044
Joint Director Industries	236113	
Kumaun Mandal Vikas Nigam	236209	235700
Labour Commissioner, Haldwani	222032	282805
MSME-DI, Haldwani	221053	228353
S.S.P., Nainital / Camp HLD.	235730	235693
Electronics Services & Training Centre (ESTC)	251201, 251530	251294
Kania, Ramnagar		

UDHAM SINGH NAGAR (STD Code No. : 05944)

Chief Development Officer	250450	250450
Container Corporation of India Ltd.	7060031652	
District Development Officer	250454	250454
District Magistrate	242344	242344

Important Phone Numbers of Uttarakhand Government



District Industries Centre	250273	250274
District Information Officer	250890	250890
G. B. Pant University of Agriculture & Technology	233333	233500
Mandi Bhavan	250055	
State Industrial Development Corporation Ltd. (SIDCUL)	250354	250355
Sr. Superintendent of Police	243907	243011

KASHIPUR (STD Code No. : 05947)

Addl. Superintendent of Police	261236		
C. O.	275077		
Design Centre	272263		
Hospital (L. D. Bhatt Hospital)	278443, 102		
Industrial Training Institute (ITI)	262113		
Indian Institute of Management	211920		
Income Tax Office	275884		
Jal Nigam	274278		
KGCCI	262478	262078	
Kotwali	274015, 100		
LIC Office	274218		
Mayor, Nagar Nigam	275514	9837027894	
Mandi Samiti	275179		
National Small Industries Corporation (NSIC)	262453		
Polytechnic	274034		
Police Station, ITI	262424	9917055122	262062
Public Works Department (PWD)	275236		
Post Office	274212		
Railway Station	274027, 131		
Roadways	275327		
Shri K. C. Singh Baba, Ex. M. P.,	272327	9412088886	
Shri H. S. Ceema, MLA, Kashipur		9412090555	
Shri Rajeev Agarwal, Ex. MLA		9837046006	
Sub District Magistrate	274023		
Telephone	274197, 197		
Tehsildar	274026		
Uttarakhand Power Corporation Ltd.	261259		

ALMORA (STD Code No. : 05962)

Chief Medical Officer	230015	230015
Chief Development Officer	230027	231264
District Magistrate	230170	230435
Dy. Superintendent of Police	230007	
District Industries Centre	230177	
District Horticulture Officer	230082	
District Information Officer	230209	230209
District Forest Officer	230065	
Executive Engineer, UPCL	230114	
Executive Engineer, PWD	230091	
Regional Tourist Officer	230180	
Superintendent of Police	230007	230036

PITHORAGARH (STD Code No. : 05964)

Chief Medical Officer	225142	225504
Chief Development Officer	225336	225336
District Development Officer	225097	225097
District Information Officer	225549	225549
District Industries Centre	223574	
District Horticulture Officer	225275	225275
Divisional Forest Officer	225234	225234
District Magistrate	225301	225001
Superintendent of Police	225539	225023

CHAMPAWAT (STD Code No. : 05965)

Chief Development Officer	230550	230345
District Magistrate	230285	230295
District Industries Centre	230082	230528
District Information Centre	230790	230790
Executive Engineer, PWD	230034	230034
Superintendent of Police	230276	230515

CHAMOLI (STD Code No. : 01372)

Additional District Magistrate	253785	
Chief Development Officer	253419	235419
Chief Agriculture Officer	253912	253912
District Development Officer	252103	252103
District Horticulture Officer	253635	253635
District Information Office	252496	252496
District Industries Centre	252126	252126
District Magistrate	252102	252203
Executive Engineer, PWD	252173	252173
Superintendent of Police	252134	252134

TEHRIGARHWAL (STD Code No. : 01376)

Chief Development Officer	232603	232080
District Magistrate	232092	232354
District Industries Centre (N. Nagar)	227297	227297
District Information Officer	232231	232231
District Development Officer	232603	232603
District Horticulture Officer	232156	
Superintendent of Police	232162	232162

PAURI (STD Code No. : 01382)

Chief Development Officer	222920	221793
District Magistrate	222250	222811
District Industries Centre (Kotdwar)	222266	222266
District Tourism Officer	222241	222241
District Information Officer	222283	222283
Superintendent of Police	222254	223438

Bageshwar (STD Code No. : 05963)

Chief Development Officer	220858	220570
Chief Medical Officer	221026	221538
District Magistrate	220763	220328
District Information Officer	221011	221011
District Industries Centre	221476	
Divisional Forest Officer	220249	
Executive Engineer, PWD	220006	
Executive Engineer, UPCL	221262	
Kumaun Mandal Vikas Nigam	220034	
Superintendent of Police	220382	220382

Uttarkashi (STD Code No. : 01374)

Chief Medical Officer	222106	222106
Chief Development Officer	222724	222724
District Magistrate	222280	222119
District Industries Centre	222744	222744
District Information Officer	222213	222213
District Horticulture Officer	222143	222143
Divisional Forest Officer	222444	222444
Superintendent of Police	222116	222116

Rudraprayag (STD Code No. : 01364)

Chief Development Officer	233189	233711
Chief Medical Officer	233841	233946
Chief Agriculture Officer	233260	233260
District Horticulture Officer	233416	233416
District Information Officer	233871	233871
District Magistrate	233300	233380
District Industries Centre	233119	233119
Superintendent of Police	233387	233387

Haridwar (STD Code No. : 01334)

Chief Development Officer	239097	239097
Chief Medical Officer	226023	226023
Chief Agriculture Officer	239034	239034
District Horticulture Officer	239062	239062
District Development Officer	239001	239001
District Information Officer	226695	226695
District Magistrate	239440	239380
District Industries Centre (Roorki)	262452	261929
Superintendent of Police	239777	239777

CHAMBERS

- | | |
|---|--|
| • Associated Chambers of Commerce
& Industry, New Delhi | 46550555 (Hunting)
Fax : 011 - 23017008 |
| • Confederation of Indian Industries (CII)
New Delhi | 45771000 / 24629994-7
Fax : 011 - 24626149 |
| • FICCI, New Delhi
(KGCCI in affiliation with) | 23738760 to 70, 23736297
Fax No. : 23320714 |
| • PHD Chamber of Commerce & Industry
New Delhi (KGCCI in affiliation with) | 26863801-04
Fax No. : 26855450, 49545451 |



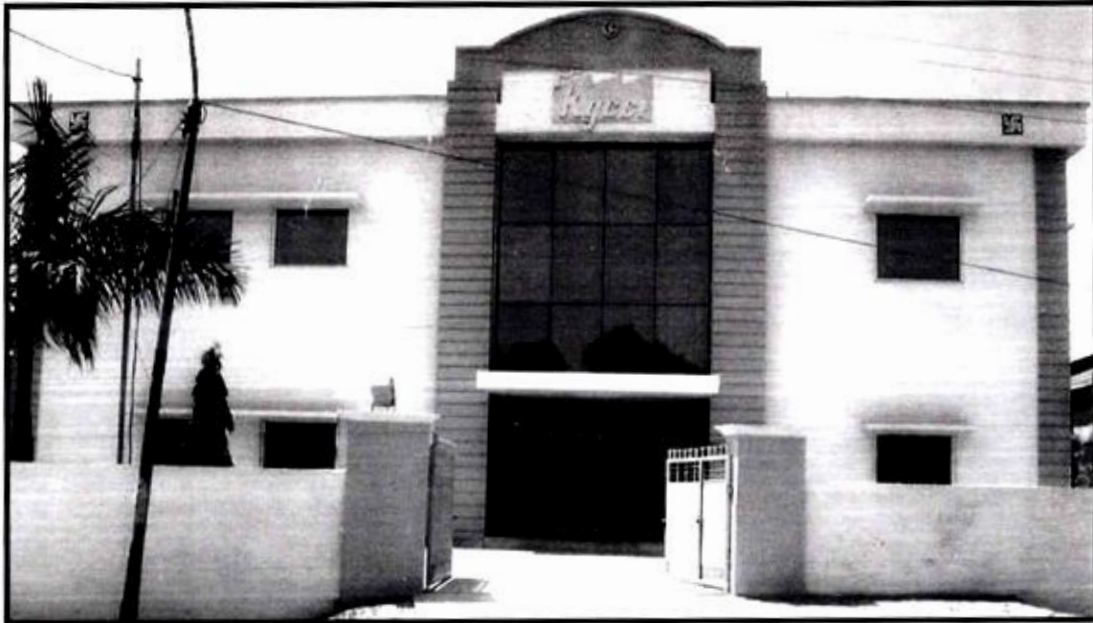
APPLICATION FORM
For
Ordinary Membership

For Chamber Use

Membership No.

Aproved on

Membership Registration Category



Kumaun Garhwal Chamber of Commerce & Industry

Chamber House, Industrial Estate, Bazpur Road, Kashipur - 244713

Distt. udham singh nagar (UTTARAKHAND)

Phone : (05947) 262478

E-mail : kgcci10@gmail.com, Web Site : www.kgcci.in

Our Endeavour : Growth of Industry - For Prosperity of Uttarakhand

Registration of Membership

To,
The Secretary General
Kumaun Garhwal Chamber of Commerce & Industry
"Chamber House" Industrial Estate
Bazpur Road
Kashipur (U.S. Nagar) Uttarakhand

Date :

Dear Sir,

We wish to apply for the ordinary Membership of KGCCI and request you to place our duly filled application form before the Managing Committee for their perusal & acceptance. The relevant supporting documents are also enclosed.

Please find enclosed Cheque/D.D. No.....Date for Rs..... Drawn on in favour of KGCCI payable at Kashipur, Distt U. S. Nagar (Uttarakhand) towards the Annual Subscription for the year and one time Registration Fee (As per KGCCI tariff printed at backside of the Form).

We hereby give our consent to abide by Memorandum, article of association, the Rules and Regulations of the Chamber.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully

(Signature)
Name & Designation
with Seal

Proposed by _____
(Signature of Authorised Representative)

(Name of the member - firm)

Seconded By _____
(Signature of Authorised Representative)

(Name of the member - firm)

Necessary to be
proposed
and
seconded
by
two members
of the Chamber

- 9) Year of establishment/Commissioning : _____
- 10) Company Data (Please attach latest Annual Report/Audited A/cs/profit loss A/c.) : _____
- 11) a. Capital Investment in Plant & Machinery: Rs. _____
 b. Turnover (Last two years) : Rs. _____ in year _____
 : Rs. _____ in year _____
 c. No. of employees (Approx.) : _____
 d. Audited Copy of last Balance Sheet : _____
- 12) Status of Export house/Trading house/ : Export turnover _____
 Super trading house/E.D.U./E.P.Z. Year _____
 Major export Mkt. _____
- 13) Existing Membership of any other Chamber/any association : _____

Signature : _____ Name : _____

Date : _____ Designation : _____

FEE PAYABLE :

Category	Investment	Annual Subscription	Registration Fee
(a)	Total Investment upto Rs. 5 crore	Rs. 6,000/-	Rs. 2,500/-
(b)	Total Investment upto Rs. 10 crore	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-
(c)	Total Investment upto Rs. 20 crore	Rs. 20,000/-	Rs. 5,000/-
(d)	Total Investment upto Rs. 50 crore	Rs. 30,000/-	Rs. 10,000/-
(e)	Total Investment upto Rs. 75 crore	Rs. 40,000/-	Rs. 10,000/-
(f)	Total Investment upto Rs. 100 crore	Rs. 50,000/-	Rs. 15,000/-
(g)	Total Investment upto Rs. 250 crore	Rs. 75,000/-	Rs. 20,000/-
(h)	Total Investment above Rs. 250 crore	Rs. 1,00,000/-	Rs. 25,000/-

Definition of Total Investment :

The investment made against Land, Building and Plant & Machinery.



Printed for and on behalf of :

KUMAUN GARHWAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

"CHAMBER HOUSE" Industrial Estate, Bazpur Road, Kashipur-244713

Udham Singh Nagar (Uttarakhand), India

Phone : 05947 - 262478

E-mail : kgcci10@gmail.com, website : www.kgcci.in

Branch Office :

Source Automotive Parts

Plot No. 30, Sector- I I D C, I.I.E., SIDCUL, Pantnagar

Rudrapur (U. S. Nagar), Uttarakhand

Editor

Nitin Agarwal

Secretary General

The informations published are based on Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh (HP) & Uttarakhand, 2017 received from Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Govt. Of India, New Delhi. Although every effort has been made to ensure correctness of data, omissions & errors. If any, are exempted, editorial staff, printers, publishers and designer shall not be responsible for any mistake and consequences there to.



THE ALL NEW MANOR WITH NEW ROOMS, FITNESS CENTRE & A SPA




THE MANOR
KASHIPUR
where business is pleasure

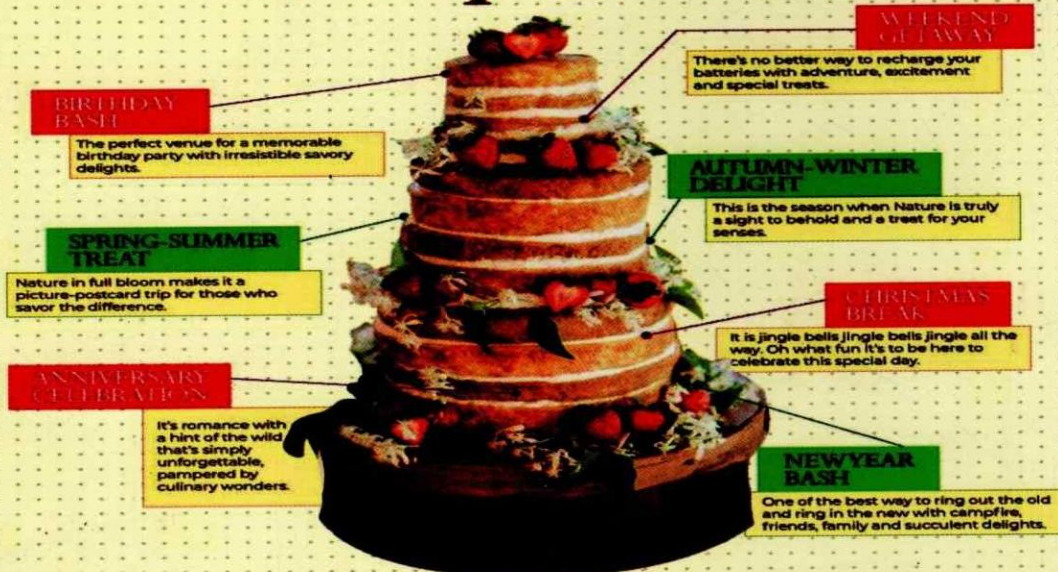
Near Chaiti Chauraha, Bazpur Road, Kashipur
Ph. (05947) 262985/86, 9359926907
Email : kashipur@leisurehotels.in
www.leisurehotels.in



IRIS
Resorts

CORBETT WILD IRIS SPA & RESORTS

WHATEVER BE THE OCCASION.



IRIS IS THE PLACE TO BE FOR THE RIGHT REASON

Your perfect take off point for a trip to the Corbett National Park,
Iris Resort combines the pristine charm of the un-spoilt wilderness with
the facilities and amenities of modern living. So you get to enjoy the best of both worlds.
JUST THINK OF AN EXCUSE TO INDULGE.

>> BOOK NOW <<

#trystwithiris

www.irisresorts.com

For reservations, please contact us at:
+91-9643331023, +91-9643331025
info@irisresorts.com

